भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1228

जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

25 अग्रहायण, 1944 (शक)

आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका सत्यापन

1228. श्री बृजलाल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न संस्थाओं को आधार का सत्यापन करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या प्राधिकरण ने प्रमाणन और सत्यापन करने के लिए अधिकृत संस्थाओं को कोई परिपत्र भी जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): आधार के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आधार धारक की पहचान को प्रमाणित करने और उसके द्वारा सत्यापित करने के लिए एक आसान, ऑनलाइन और सुरक्षित तंत्र प्रदान किया है।

आधार के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए, प्राधिकरण ने आधार (प्रमाणीकरण और ऑफ़ लाइन सत्यापन) विनियम, 2021 में 4.2.2022 को संशोधनों को भी अधिसूचित किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑफ़ लाइन सत्यापन की मांग करने वाली कोई भी संस्था पहले प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित किए बिना भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से (प्रमाणीकरण के बिना) आधार संख्या, वैध उद्देश्य के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेगी।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने 26.9.2022 को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और प्रशासनों को लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि पंजीकरण के समय संपत्तियों की या उच्च-मूल्य वाले

वित्तीय लेनदेन को निष्पादित करते समय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग संस्थाओं द्वारा किया जाए।

प्राधिकरण ने 31.10.2022 को परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन प्रमाणीकरण और ऑफ़ लाइन सत्यापन का अनुरोध करने वाली संस्थाओं के लिए क्या करें और क्या न करें की जानकारी दी गई है। इसमे प्रावधान है कि इन संस्थाओं को किसी निवासी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार को सत्यापित करना चाहिए।

******